International Journal of Education and Science Research Review
E- ISSN 2348-6457
Volume-1, Issue-3 June- 2014 P- ISSN2349-1817
WWW.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

राजीव गांधी के समय भारत–चीन सम्बन्ध (1984–1989 तक)

ज्योति
रिसर्च स्कॉलर
राजनीति शास्त्र विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली

सार

चीन के प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री का पद संभालने और सरकार के गठन के शुभ अवसर पर अपना बधाई संदेश भेजा। 1984 में श्रीमती गांधी की मृत्यु के पश्चात् चीन के उप–प्रधानमंत्री चाओ–ली–लीन भारत आए और भारत चीन के सम्बन्धों को मधुर बनाने का आश्वासन दिया। 28 फरवरी 1985 को चीन का आठ सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल अनेक क्षेत्रों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा भारत व्यापार को बढ़ाने के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए दिल्ली पहुँचे। मार्च व अप्रैल 1985 में तत्कालीन विदेश सचिव रमेश भंडारी कई पड़ोसी देशों की यात्रा पर गए उन्होंने चीन के प्रति यह स्पष्ट किया कि भारत–चीन के मैत्री सम्बन्धों में एक मुख्य बाधा सीमा विवाद बना हुआ है।

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह निर्णय लिया कि वे अपने पड़ोसी राज्यो के साथ मित्रता एवं सहयोगात्मक सम्बन्धों को विकसित करने के लिए एक प्रमुख अभियान चलाएगें। ''भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्री व सहयोगात्मक दृष्टिकोण का सुखद प्रभाव हुआ तथा आस–पास और दूर के देशों से भारत के सम्बन्धों में ताजी, शीतल, सकारात्मक हवा का झोंका महसूस हुआ।'' तथापि दुर्भाग्य से चीन (1985–88) के साथ हमारे सम्बन्ध वैसे ही बने रहे।

इस प्रकार खुली विचारधारा और भारत की वचनबद्धता होते हुए भी चीन अपनी पुरानी नीति एकमुश्ती सौदे द्वारा सीमा–विवाद को हल करने से पहले सामान्यीकरण पर रहा। जुलाई, 1985 में चीन ने यह सुझाया कि भारत को ल्हासा में अपने मिशन को पुनः खोलना चाहिए एवं बदले में चीन, कलकत्ता और किसी अन्य क्षेत्र पर अपने मिशन खोलेगा किंतु, भारत ने चीन के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि चीन वास्तविक समस्या सीमा विवाद को हल किए बिना सम्बन्धों को सामान्या बनाना चाहता है।

कुलदीप नैय्यर ने 13 जुलाई, 1985को दी ट्रिब्यून में एक उच्चस्तरीय स्रोत के हवाले से यह लिखा कि, ''ल्हासा में अपना मिशन पुनः खोलने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न ही हमें 1962 के चीन आक्रमण से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। चीन ने जिस भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया हुआ है पहले उस क्षेत्र को भारत को वापस करना चाहिए।'' भारत–चीन सम्बन्धों को सामान्य करने हेतु भारत–चीन के मध्य कई वार्ताओं के दौरे होने के बावजूद भी सीमा विवाद समस्या को हल करने के लिए बहुत कम सफलता मिली। अक्तूबर, 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और चीन के प्रधानमंत्री जोया जीयांग के मध्य न्यूयार्क में वार्ता हुई। 4 नवम्बर 1985 में भारत–चीन वार्ता का छठा दौर दिल्ली में संपन्न हुआ। इस वार्ता में पूर्वी क्षेत्र में सीमा निर्धारिण के प्रश्न पर कुछ प्रगति हुई, पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों देशों के मध्य् पश्चिमी क्षेत्र का अधिक महत्व है यहीं पर लद्दाख में चीन ने अस्थाई सड़क बनाई है। पाकिस्तान व भारत की सेनाओं के मध्य सियाचिन ग्लेशियर पर झड़पें हुई हैं। चीन की ये मंशा है कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान अपना वैध कब्जा कर चीन को दे दे। इससे सिकियांग में व रूस के विरूद्ध जल सामरिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वार्ता की प्रगति की रफ्तार निश्चित रूप से अत्यंत धीमी है। अन्य क्षेत्रों में दोनों पक्ष आपसी सम्बन्ध बढ़ाने को सहमत हो जाए। वार्ता के द्वारा बीजिंग में भारतीय दूतावास के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए लंबे विवाद का सुलझ जाना एक उपलब्धि थी। 1967 में चीन ने भारतीय दूतावास की जो सम्पत्ति जब्त की थी इसका मुआवजा देने का भी निर्णय किया। चीन भारतीय दूतावास के लिए 3400 वर्गमीटर भूमि देने को सहमत हो गया। यह भूमि दीर्घकालीन पट्टे पर बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध कराई गयी। दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास पर काफी स्पष्ट वार्तालाप हुआ। कृषि, शिक्षा, कम्प्यूटर, उघोग, प्लाज्मा, भौतिकी तथा बायो तकनीक के क्षेत्रों में शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान का भी समझौता हुआ। इस बात का भी निर्णय किया गया कि चीन सामाजिक–आर्थिक योजना पर एक संयुक्त सेमिनार आयोजित किया जाए। परंतु सीमा–विवाद के हल न होने के कारण वार्ता सीमित ही रही।

23 नवम्बर, 1985 को भारत–चीन के मध्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत वर्ष 1986 के दौरान दोनों देशों में 10 से 14 करोड़ का व्यापार होना तय किया। इस दौरान संतुलन चीन के पक्ष में था। 1984–1985 में भारत ने चीन से 65.55 करोड़ रुपए का कच्चा और तैयार माल आयात किया था जबकि उसका निर्यात केवल 2.12 करोड़ रुपए का था। नए समझौते से व्यापार संतुलन स्थापित होने की आशा प्रकट की गई।
अधिकारी स्तर वार्ता का सातवां दौर 21–23 जुलाई, 1986 तक बीजिंग में संपन्न हुआ। सीमा सम्बन्धी मसले पर, नई दिल्ली में नवम्बर, 1985 में वार्ता के छठे दौर में विचार–विमर्श प्रारंभ किया गया तथा सारभूत विचार–विमर्श पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी रखा गया। हालांकि विचार–विमर्श किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा फिर भी एक–दूसरे के विचारों को और अधिक अच्छी तरह समझने का मौका प्राप्त हुआ। विज्ञान और प्रौघोगिक के क्षेत्र में आदान–प्रदान सम्बन्धी एक कार्यक्रम तय किया गया। सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने अंतर्राश्ट्रीय स्थिति पर विचार–विमर्श किया। वार्ता के सातवें दौर में चीन के अरूणाचल प्रदेश में तवांग जिले के समुदोराम धू घाटी क्षेत्र में उसकी घुसपैठ पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया। 18 सितम्बर, 1986 को न्यूयार्क में भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी उठाया गया।

इस दौर में सरकारी आयात निर्यात कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों के मध्य शिक्षा, प्रौघोगिकी, छात्रवृत्ति आदि के क्षेत्रों में बहुत से प्रतिनिधिमंडल परस्पर रूप से देशों में भेजे। चीन के उप–शिक्षा मंत्री के नेतृत्वे में एक शिक्षा प्रतिनिधिमंडल भारत आया। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ऑफ चाइना के अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के आमंत्रण पर भारत की यात्रा की। वी.के. कृष्णमेनन सोसायटी के आमंत्रण पर चीन अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना संघ परिषद् सदस्य श्री ली.वी. हाई के नेतृत्व में 28 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1986 तक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। भारत की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आमंत्रण पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्पर्क विभाग के उपाध्यक्ष याओ ईलान के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्पर्क सूचना विभाग के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19 से 31 दिसम्बर, 1986 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्लीं में कांग्रेस(आई) के नेताओं से भी विचारों का आदान–प्रदान किया।

20 फरवरी, 1987 को भारत–सरकार ने अरूणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वां राज्य घोषित कर दिया। इस पर चीन ने भारत से आपत्ति उठाई कि इस कार्यवाही से चीन की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता का गंभीर उल्लंघन हुआ है। इसके विपरीत भारत का मानना है कि पंचशील सिद्धांत के आधार पर यह देश का अपना आंतरिक मुद्दा है इसमें चीन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इससे पहले चीन ने अरूणाचल प्रदेश के विषय में विवाद को बढ़ाया था। 1987 के शुरूआती दौर से ही चीन का व्यवहार फिर से अप्रत्यक्ष रूप से कठोर होता नजर आया और भारत को सबक सिखाए जाने की सूचना प्राप्त होती नजर आई। चीन ने अनेक बार बेबुनियाद आरोप लगया कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण कर चीनी क्षेत्र में घुस आई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के आरोपों को बेबुनियाद, काल्पनिक कहते हुए कहा कि ''भारत ने चीन की सीमा के निकट कोई सैनिक अभ्यास ही नहीं किया।'' भारतीय सेना को विदेश मंत्रालय से यह भी निर्देश दिया गया था कि वह भारत–चीन की वास्तविक सीमा को पार न करे। 14 से 16 जून, 1987 तक भारत के विदेशमंत्री के.पी.एस. मेनन ने अनौपचारिक चीन यात्रा की और चीनी नेताओं से सीमा पर शांति सुरक्षा बनाए रखने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ''दोनों देशों द्वारा सीमा पर शांति, सुरक्षा बनाए रखी जाने की अपील की।'' उन्होंने पश्चिमी प्रेस में प्रकाशित सूचनाओं, विषयों को बेबुनियादी करार दिया तथा स्पष्ट किया कि तिब्बत पर भारत–चीन के सैनिकों के मध्य नोक–झोंक हो चुकी है।''
27 मई, 1987 को भारत तथा चीन में एक और व्यापार समझौता हुआ, इस व्यापार समझौते के द्वारा जनवरी, 1987 से मार्च, 1988 के मध्य व्यापार 150–200 मिलीयन डालर तक बढ़ाने का निर्णय किया। इस समझौते में भारत से कच्चे लोहे को चीन भेजने की व्यवस्था थी।

चीन कभी अरूणाचल तो कभी सिक्किम को लेकर विवाद को उभारता रहता है पाकिस्तान और अमेरिका के साथ चीन का गठबंधन है उसका प्रमुख पहलू भारत पर राजनीतिक, तकनीकी और सैनिक दबाव बनाए रखना है। पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम राजमार्ग के उत्तरी स्तर पर चीन द्वारा निर्मित 4620 मीटर लंबा खुजराव मार्ग विधिवत खुल जाने से यात्रा और व्यापार की दृष्टि से चीन और पाकिस्तान एक–दूसरे के करीब आए। पाकिस्तान को चीन से भारी मात्रा में परमाणु हथियार और अन्य हथियार मिलते रहे हैं। भारत–चीन सम्बन्धों तथा सीमा वार्ताओं में आए गतिरोधों को दूर करने के लिए भारत ने अधिकारी स्तर की वार्ता को राजनीतिक वार्ता में परिवर्तित करने का निर्णय किया, इसलिए तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ''नाम'' कांफ्रेंस से आते हुए बीजिंग रूके। चीनी विदेश मंत्री से लंबी वार्ता हुई तिवारी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि ''हम चाहते हैं चीन के साथ मित्रतापूर्ण तथा सामान्यीकरण के आश्वासनों की समीक्षा की जाए, हम अपने सभी मतभेदों का, सीमा–विवाद को शामिल करके, वार्ता द्वारा हल करना चाहते हैं। श्री तिवारी कुछ सीमा तक चीनियों को यह समझाने में सफल रहे कि दोनों देशों को पूर्ण सामान्य सम्बन्ध तथा मित्रता व सहयोग को बढ़ाने के लिए निश्चयपूर्वक

प्रयत्न करने चाहिए। सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर बने सम्पर्को के वजाय यह वार्ता आशा तथा सद्भावना के वातावरण में हुई। चीनियों ने द्विपक्षीय सम्बन्धों में आए तनाव और डर को दूर करने का प्रयत्न किया। सहमति हुई कि सीमा विवाद के समाधान के प्रयास शांति पूर्ण तथा विवेकपूर्ण तरीके से जारी रखे जाऐंगे।

भारत–चीन अधिकारी स्तर की वार्ता का आठवां दौर 17 नवम्बर, 1987 को दिल्ली में आयोजित हुआ परंतु हाल वही ''नौ दिन चले अढ़ाई कोस'' अर्थात् भारत–चीन सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में लेशमात्र प्रगति नहीं हुई। चीन की इच्छा थी कि पूर्वी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाकर एक असैन्य कृत क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाए, किंतु भारत सोमदोरोंगे चू घटी में चीन के आक्रमण को भुला नहीं पाया तथा उसने यह खतरा उठाना ठीक नहीं समझा। इस वार्ता की एकमात्र उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि दोनों पक्षों ने यह निश्चय किया कि सीमा पर शांति भंग नहीं की जाएगी। 28 मई 1988 को भारत–चीन ने बीजिंग में पहले सांस्कृतिक सहयोग पर हस्ताक्षर किये।

भारत–चीन के सम्बन्धों में सकारात्मक प्रोत्साहन उस वक्त प्राप्त हुआ जब एक साहसिक तथा सुखद प्रयत्न भारत द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत–चीन सम्बन्धों को सुधारने और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जिनमें से महत्वपूर्ण कदम 19 से 22 दिसम्बर, 1988 में उनकी चीन यात्रा थी। राजीव गांधी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों की नई कड़ी का सूत्रपात हुआ। यह एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इससे पूर्व चीन के प्रधानमंत्री चाऊ–एन–लाई 25 जून, 1954 को भारत की यात्रा पर आए तथा 18 अक्तूबर, 1954 में नेहरू ने भी चीन की यात्रा की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रधानमंत्री ली–पेंग की उच्च स्तरीय चीन की यात्रा 34 वर्ष के अंतराल के पश्चात् हुई। भारत चीन सम्बन्धों में इस यात्रा से एक नवीन आरंभ का प्रादुर्भाव हुआ तथा इन दोनों देशों में इस यात्रा के दौरान जिन दिशा निर्देशों को तैयार किया, उनके आधार पर सम्बन्धों का विकास शुरू हुआ। इसके दौरान चीनी नेता डेंग जियोपिंग ने घोषणा की कि, ''हमारे सम्बन्धों के सुधार को इस यात्रा से ''वास्तविक आरंभ'' प्राप्त है और यह यात्रा हमारे सम्बन्धों के विकास की और अधिक प्रोत्साहन देगी।''

श्री राजीव गांधी का स्वागत् करते हुए श्री डेंग जीयोपिंग ने कहा, ''मेरे युवा मित्र तुम्हारा अत्यधिक स्वागत् है आपकी यात्रा से आरंभ कर हम अपने सम्बन्ध पुनः मैत्रीपूर्ण बना लेंगे तथा दोनों देशों के नेताओं के मध्य मित्रता मजबूत होगी, मित्रता के साथ दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण, मजबूत हो जाएंगे। ।''

राजीव गांधी का यह पूर्ण विश्वास था कि भारत–चीन अकेले और साथ–साथ अपने लिए एवं पूर्ण विश्व के प्रति बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''हमारे सम्बन्ध मानवता के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत–चीन अपने सम्बन्धों में सुधार न सिर्फ आपसी फायदे के लिए चाहते हैं, बल्कि एक ऐसा आधार प्रदान करने हेतु भी चाहते है, जो एक नई विश्व प्रणाली के सृजन में भी योगदान दें।'' भारत–चीन के सम्बन्धों में आए स्थायित्व को गतिशीलता राजीव गांधी की चीन यात्रा से प्राप्त हुई। राजीव गांधी ने यात्रा के दौरा किनशुआ विश्व विघालय में स्पष्ट किया –

मुझे यह विश्वास है कि इस यात्रा से भारत–चीन सम्बन्धों को नई दिशा प्राप्त होगी। इस यात्रा से हम अपने चीनी मित्रों के सहयोग के द्वारा सीमा–विवाद का समाधान व शांति का वातावरण स्थापित करने में कामयाब होंगे। दोनों देश नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए आपसी सहयोग से कार्य करेंगे।

इस अवसर पर चीन के नेता वेग के शब्द महत्वपूर्ण रहे, ''काफी समय से भारत–चीन सम्बन्धों व सुधारों से मधुर हो रहे हैं तथापि भारत–चीन मैत्री की वास्तविक शुरूआत आपकी इस चीन यात्रा से हो रही है।''

भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दिसम्बर, 1988 की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात् नियमित सम्पर्क में वृद्धि, अंतर्राश्ट्रीय व्यवस्था में आए परिवर्तन, चीन–रूस मैत्री की प्रक्रिया की उत्पत्ति शीत युद्ध की समाप्ति, भारत सरकार की यह नीति कि पड़ोसियों के साथ सुखद सम्बन्धों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, चीन का कश्मीर पर तथाकथित बिचोलिये की भूमिका से इंकार तथा कश्मीर समस्या पर कुछ परिपक्व दृ ष्टिकोण, ये सब भविष्य में अच्छे भारत–चीन सम्बन्धों के लिए स्वस्थ्य पद चिन्ह बने।

भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि ''भारत–चीन के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का हल होना दोनों देशों की मैत्री की बुनियादी शर्त नहीं है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता सीमा–विवाद की समस्या के समाधान के लिए ''संयुक्त कार्यदल'' की स्थापना करना रहा। यह भी निर्णय लिया गया कि ''संयुक्त कार्यदल'' समूह की अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव तथा चीन के विदेश कार्य के उपमंत्री करेंगे। यह कार्यदल सीमा विवाद को एक निश्चित सीमा अवधि में सुलझाने का सुझाव व प्रयास करेगा, यह दल वास्तविक रेखा के साथ–साथ शांति, सुरक्षा बनाएगा, तथा वैकल्पिक रूप से कार्यों के लिए हर छः माह में बैठक होगी और ये बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली या चीन राजधानी बीजिंग में होगी। इसके साथ दिपक्षीय विषयों पर अन्य समझौते किए गए :–

भारत–चीन ने यह भी सहमति व्यक्त की कि वे अपने मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगत्मक सम्बन्धों के विकास को बनाए रखेगें तथा साथ ही साथ सीमा विवाद के प्रश्नो का भी हल खोजते रहेंगे। सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत तथा चीन ने यह निर्णय लिया कि एक संयुक्त कार्य प्रचलन समूह का निर्माण किया जाए जिसका भारत की ओर से सभापत्तिव विदेश सचिव द्वारा किया जाएगा तथा चीन की ओर से विदेश मामलों के उपमंत्री द्वारा। इसका कार्य सीमा–विवाद के एक निश्चित कालावधि में सम्पूर्ण समाधान के लिए ठोस सिफारिशें करना तथा विज्ञान तथा प्रौघोगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता तथा द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग समझौते के अंतर्गत 1988, 1989, 1990 के वर्षों के लिए कार्यकारी प्रोग्राम तैयार करना था। 23 दिसम्बर, 1988 को एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें कहा गया कि ''दोनों देश पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर ही आपसी सम्बन्ध कायम करेंगे। राजीव गांधी की इस यात्रा से सीमा–विवाद सुलझाने तथा सहयोग के अन्य क्षेत्रों में प्रगति हुई। राजीव गांधी की इस यात्रा ने चल रहे पिछले गतिरोधों का अंत किया। अन्ततः कहा गया कि एशिया के बड़े देशों में निकट पड़ोसियों जैसे तथा मित्रतापूर्वक सम्बन्धों की स्थापना इस महाद्वीप में स्थिरता व शांति ला सकती है। इससे भारत–चीन सीमा विवाद भी हल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने यह सहमति प्रकट की और माना कि यह उनकी सांझी इच्छा थी कि इन सिद्धांतों के आधार पर भारत चीन के अच्छे पड़ोसियों जैसे तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को पुनः स्थापित किया जाए तथा सम्बन्धों में सुधार से मैत्री व मैत्री से विकास किया जाए। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अपनी पहल पर चीन की यात्रा की कुछ सूत्रों द्वारा आलोचना की गई।

चीन की यात्रा से चीन–भारत सम्बन्धों, जहां तक सीमांत क्षेत्र में शांति तथा प्रशांति बनाए रखने के समझौते को किया जा सका तथा निर्णय किया कि सीमा विवाद की चुनौती का सकारात्मक रूप से सामना करने के लिए एक संयुक्त कार्य संचालन समूह का गठन किया जाए, सफलता प्राप्त होगी। 29 जून, 1954 से लेकर पंचशील में चीन तथा भारत द्वारा विश्वास की पुष्टि एक प्रथा का रूप ले चुकी थी तथा राजीव गांधी की यात्रा ने भी इन सिद्धांतों को आधार माना। सीमा विवाद पर संयुक्त कार्य संचालन समूह के गठन के विषय में समझौते के अनुसार 6–8 जुलाई, 1989 को कार्य संचालन हेतु बैठक बीजिंग में आयोजित हुई। वार्ता के तीन दौरों के संचालन में अनेक द्विपक्षीय मामलों पर, विशेष तौर पर जटिल सीमा विवाद पर मैत्रीपूर्ण, सद्भावना तथा मुक्त विचार विमर्श किया गया। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्री एस.के.सिंह, जिन्होंने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया, ने इस अवसर का लाभ चीनी प्रधानमंत्री वी–पेंग तथा विदेश मंत्री क्रियान की चेन से मिलने के लिए उठाया। चीनी नेताओं ने तिनानमेन स्कवेयर की घटना पर भारत द्वारा प्रदर्शित किए गए संयम की प्रशंसा की और उन्होंने भारत के साथ सशक्त निकटता के सम्बन्धों के विकास की इच्छाए श्री एस.के. सिंह के सम्मुख व्यक्त की।

कार्य संचालन दल की प्रथम बैठक के पश्चात् यह स्पष्ट घोषणा की गई कि ''भारत–चीन ने जटिल सीमा प्रश्न के ''शीघ्र समाधान'' हेतु अपने सच्चे निश्चय की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने व्यापार तथा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रौघोगिक सम्बन्धों में विविधता लाने, प्रचार, प्रसार हेतु ठोस कदम उठाने का निश्चय भी किया गया है।''

अतः 1989 के वर्षों में दोनों देशों ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाए रखे। दोनों ने 20 सितम्बर, 1989 में एक आलेख पर हस्ताक्षर किए। तथापि सीमा–विवाद पर चीन–भारत के मध्य कोई प्रमुख समझौता नहीं हो पाया। इस प्रकार श्री राजीव गांधी द्वारा पड़ोसी राष्ट्र के साथ अच्छे सम्बन्धों का कड़ा प्रयास था जिससे भारत–चीन सम्बन्ध एक लंबे समय के पश्चात् सामान्य हो सका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 भारत वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 1984, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की गवेषण और संदर्भ प्रभाग द्वारा संकलित **''इंडिया 1985 का हिन्दी रूपांतरण''** प्रकाषन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 799
2 **दा ट्रिव्यून 13 जुलाई, 1985,** कुलदीप नैय्यर
3 गणेश्वर चतुर्वेदी, **इंडिया चाईना रिलेशंस 1947 से आज तक**, एम.जी. पब्लिशर, आगरा, 1991 पृष्ठ–170
4 वर्शिक रिर्पोट–1984, पृष्ठ–839
5 भारत–सरकार, **नोट्स मेमोरेण्डम एंड लेटरज**, एक्सूचेंज्डर एंड एग्रीमेंट साईंड विटविन दा गर्वनमैंट ऑफ इंडिया एंड चाईना, 1985–86, नई दिल्ली, 1986 पृष्ठ– 50–51
6 स्वर्ण सिंह, **''चाइना–इंडिया एक्स पैडिंग इकोनोमिक एगेंज्मैंट'',** स्ट्रेटजिक एनेलिसिस, 24(10) जनवरी 2001, पृष्ठ–1818
7 वर्श–1987, पृष्ठ–584
8 1986–87 तक के एशियन रिकार्डर से संकलित, इंडिया टूडे, 20 सितम्बर, 1986
9 भारत–चीन के दौरे, विचारों, पत्र सम्बन्धी जानकारी के लिए, वी.के. कृष्णमेनन सोसायटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, **''एशियन स्ट्रेनटेजिक रिव्यू नवम्बर–दिसम्बर, 1986'',** नई दिल्ली 1987
10 15 डॉ दुर्गादास वासु, **भारत का संविधान – एक परिचय दिल्ली 2011,** पृष्ठ 463

11 आर. एस. यादव, **भारत की विदेशनीति, एक विश्लेषण**, किताब महल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2004 पृष्ठ–67
12 जसजीत सिंह, **"ट्रेडज इन डिफेंस एक्सपैडिचर",** एशियन स्ट्रेटेजिक रिव्यू, 1987 नई दिल्ली 1987 पृष्ठ 25–30
13 इक्नोमिक्स टाईम्स, 10 मई 1987
14 भारत चीन इकोनोमिक एगेन्मैस्ट – वर्श–1988–1989 पृष्ठ–663
15 चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग द्वारा 19 दिसम्बर, 1988 को बीजिंग में आयोजित किए गए राज्य भोज पर दिया गया भाषण।
16 सुरजीत मानसिंह, **इंडिया–चाईना रिलेशेज इन दा पोस्ट कोल्डवार ईरा** एशियन सर्वे, भाग–34, मार्च, 1994 पृष्ठं 285–300
17 लीपेंग, **"डिपिनंग अण्डर स्टैडिंग, फोस्टरिंग फ्रैडशिप एंड स्ट्रेयानिंग कोआपरेशन",** स्ट्रेटेजिक डाइजेसट, फरवरी,
18 2001, पृष्ठ 170–180 तथा फ्रंट लाइन 16 फरवरी, 2001
19 एशियन रिकार्डर से संकलित, 1989 पृष्ठ 20534
20 सुरजीत मान, पृष्ठ 25–26
21 आर.एस. यादव, पृष्ठ संख्या 272–273
22 दा टाईम्स ऑफ इंडिया, 24 दिसम्बर, 1988
23 मेन स्ट्रीम 6 जनवरी, 1990, पृष्ठ–33 **विजिट ऑफ राजीव गांधी**
24 दा टाईम्स ऑफ इंडिया, 9 जुलाई, 1989
25 एशियन सर्वे, भाग–34 नवम्बर, 1989